



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 श्रावण 1940 (श10)
(सं0 पटना 727) पटना, सोमवार, 30 जुलाई 2018

सं० 2प/पं०स०भ०-9-8/2018-4045/पं0रा0
पंचायती राज विभाग

संकल्प
25 जुलाई 2018

विषय :- ग्राम पंचायतों में मानदेय के आधार पर कार्यपालक सहायकों के नियोजन की स्वीकृति।

बिहार पंचायत राज अधिनियम में त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को अपने प्रदत्त दायित्वों को जन आकांक्षाओं के अनुरूप प्रभावी तरीके से सम्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत का कार्यालय सभी कार्य दिवसों में विधिवत सरकारी कार्यालयों की भांति संचालित हो। वर्तमान में ग्राम पंचायतों द्वारा केन्द्र प्रायोजित एवं राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। जिसमें ग्राम पंचायत को सहायता उपलब्ध कराने हेतु यह योजना प्रारम्भ की गई है।

2. इन सभी योजनाओं का प्रबन्धन एवं अनुश्रवण ई-पंचायत पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना की ऑनलाईन रिपोर्टिंग की व्यवस्था विकसित करने की नितांत आवश्यकता है।

3. सम्यक विचारोपरांत राज्य के सभी पंचायतों (8386) में एक-एक कार्यपालक सहायक का नियोजन करने का निर्णय लिया गया है। (जिलावार संख्यात्मक सूची संलग्न)। इन कार्यपालक सहायकों की सेवा, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के अन्तर्गत जिला पदाधिकारी के स्तर पर संधारित पैनल से ली जायेगी। इनको प्रतिमाह ₹12000/- (बारह हजार रुपये) मानदेय दिया जायेगा। उपर्युक्त पद पर मानदेय के आधार पर नियोजन करते समय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित, आदर्श रोस्टर/आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।

मानदेय के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमतीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।

इन कार्यपालक सहायकों का मानदेय के आधार पर चयन, 31.03.2020 तक के लिए होगा, जिसे आवश्यकतानुसार आगे भी जारी रखा जायेगा।

4. पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अनुदान की राशि दी जाती है जिसका उपयोग अन्य घटकों के अलावा मानव बल (Man Power) की व्यवस्था एवं ई-गवर्नेंस पर किया जाना है। इस वित्तीय वर्ष में अनुदान मद में ग्राम पंचायतों को लगभग ₹435.20 (चार अरब पैंतिस करोड़ बीस लाख रुपये) की

राशि दी जानी है। इसी राशि में से कार्यपालक सहायकों को मानदेय का भुगतान किया जायेगा। तदनुसार पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर ग्राम पंचायतों हेतु कर्णाकित अनुदान मद में से आवश्यक आवंटन जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को दिया जायेगा। जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा पंचायतों द्वारा उपलब्ध करायी गयी अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर कार्यपालक सहायकों के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

5. इस हेतु राशि का उपबंध वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य स्कीम के विपत्र कोड 16-2515001980009 के मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष- 198 ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष-0009 राज्य वित्त आयोग के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान विषय शीर्ष (i) 00093104 सहायक अनुदान वेतन (ii) 00093105 सहायक अनुदान परिसमपत्तियों के निर्माण (iii) 00093106 सहायक अनुदान गैर वेतन से किया जायेगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये एवं इसकी प्रतिलिपि बिहार के सभी विभागों एवं महालेखाकार को बिहार,पटना सूचनार्थ भेजी जाये।

आदेश से,
अमृत लाल मीणा,
सरकार के प्रधान सचिव।

जिलावार ग्राम पंचायतों में कार्यपालक सहायकों के नियोजन का विवरण:-

क्र0	जिला का नाम	जिलों में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	कार्यपालक सहायक की संख्या
1	2	3	4
1	अरवल	65	65
2	अररिया	218	218
3	औरंगाबाद	204	204
4	बाँका	185	185
5	बेगूसराय	229	229
6	भागलपुर	242	242
7	भोजपुर	228	228
8	बक्सर	142	142
9	दरभंगा	324	324
10	पूर्वी चम्पारण	405	405
11	गोपालगंज	234	234
12	जमुई	153	153
13	जहानाबाद	93	93
14	कैमूर	149	149
15	कटिहार	235	235
16	गया	332	332
17	खगड़िया	129	129
18	किशनगंज	126	126
19	लखीसराय	80	80
20	मधेपुरा	170	170
21	मधुबनी	399	399
22	मुजफ्फरपुर	385	385
23	मुंगेर	101	101
24	नालन्दा	249	249
25	नावादा	187	187
26	पटना	322	322
27	पूरुषिया	246	246
28	रोहतास	245	245

क्र०	जिला का नाम	जिलों में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	कार्यपालक सहायक की संख्या
1	2	3	4
29	सहरसा	151	151
30	समस्तीपुर	381	381
31	सारण	323	323
32	शिवहर	53	53
33	शेखपुरा	54	54
34	सीतामढ़ी	270	270
35	सुपौल	181	181
36	सिवान	293	293
37	वैशाली	288	288
38	पश्चिमी चम्पारण	315	315
	कुल	8386	8386

आदेश से,
अमृत लाल मीणा,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 727-571+300-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>